दिसंबर 2020
खंड - XXXVI | अंक - IV

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- सीएलएमवी में बुनियादी ढांचे का विकास: भारत के लिए अवसर
- चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना
- भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र
- चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातों के लिए घरेलू बाधाएं
- दुर्लभ मृदा तत्व
- चीन में बैंक के विस्तार के परिणाम और राजनीतिक उद्भव

तिमाही प्रकाशन

इंडिया एक्ज़िम बैंक

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

सीएलएमवी में बुनियादी ढांचे का विकास: भारत के लिए अवसर

सीएलएमवी क्षेत्र, आसियान का अभिन्न हिस्सा है। इसमें कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम शामिल हैं। इन देशों का यह समूह बढ़ती खपत, अनुकूल भू-रणनीतिक लोकेशन, समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और जैव विविधता और आसियान देशों में सबसे सस्ते श्रम के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

सीएलएमवी देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति

सीएलएमवी देशों की गिनती न केवल आसियान में, बल्कि वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में की जाती है। उच्च विकास को बनाए रखने के लिए नए इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने एवं विद्यमान इन्फ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन करना जरूरी है।

सड़क और रेल परिवहन

सीएलएमवी देशों की वृद्धि को बनाए रखने के लिए रेल, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डे जैसी परिवहन की मौजूदा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना जरूरी है, ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था में संपर्क सूत्र मजबूत बनें और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा में सुधार आए तथा व्यापार और ट्रांजैक्शन लागत भी कम करने में मदद मिले। पिछले दशक में कंबोडिया और वियतनाम में पक्की सड़कों में वृद्धि देखी गई है, जबकि सीएलएमवी देश अन्य आसियान देशों से अब भी पीछे हैं। सीएलएमवी देशों में लाओ पीडीआर में पक्की सड़कों का अनुपात सबसे कम है, इसके बाद कंबोडिया और म्यांमार का स्थान है। अप्रयुक्त और अपर्याप्त रेल नेटवर्क के कारण भी सीएलएमवी देशों में व्यापार में ज्यादा लागत आती है।

समुद्री और वायु परिवहन

सीएलएमवी देशों के आर्थिक एकीकरण के लिए समुद्री परिवहन आवश्यक है। अंकटाड के अनुसार, 2018 के दौरान ड्राई बल्क कैरियर द्वारा पोर्ट में बिताए गए मीडियन समय (0.12 दिन) की दृष्टि से सिंगापुर जहां 132 देशों में पहले स्थान पर रहा, वहीं म्यांमार 9.07 दिनों के मीडियन समय के साथ 129वें स्थान पर रहा। 2018 में अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में सीएलएमवी देश ब्रुनेई को छोड़कर शेष आसियान देशों से भी पीछे रहे। वहीं, पिछले दशक के दौरान, अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात में आसियान देशों में लाओ पीडीआर में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, जो देश में अन्य अनुकूल कारकों के साथ-साथ वायु परिवहन संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार का संकेत है।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

आसियान देशों में लाओ पीडीआर में प्रति 100 लोगों में सबसे कम मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन हैं। यहां प्रति 100 लोगों पर 51.9 मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन हैं, जो फिलीपींस में मोबाइल फोन सब्सक्राइबरों के आधे

से अधिक है। फिलीपींस में दूसरे सबसे कम मोबाइल फोन सब्सक्रिप्शन हैं। सीएलएमवी देश प्रति 100 लोगों पर मोबाइल-ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और फाइबर इंटरनेट सब्सक्रिप्शन के मामले में अन्य आसियान देशों से पीछे हैं। म्यांमार में केवल 23.6% आबादी और लाओ पीडीआर में 25.5% आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है। इसका अर्थ है कि सीएलएमवी देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट की पहुंच से बाहर है। सीएलएम देशों में 4जी नेटवर्क का विकास और बिजली की पहुंच अब भी महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये देश ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस के मामले में भी पीछे हैं।

यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर

कुछ आसियान देश उच्च बिजली उपभोक्ता हैं, जहां बिजली की समान पहुंच है। किन्तु म्यांमार और कंबोडिया में आज भी बिजली की समान पहुंच नहीं है। इन देशों में बिजली की पहुंच वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क से जुड़ी चुनौतियों के कारण सीमित है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। म्यांमार में केवल 54.8% ग्रामीण आबादी वर्तमान में बिजली का उपयोग कर पाती है। इसके अलावा, कंबोडिया और वियतनाम में आपूर्ति की जाने वाली कुल बिजली का क्रमशः 13% और 10.2% आपूर्ति के स्रोतों और वितरण बिंदुओं तथा उपभोक्ताओं को वितरण के बीच कहीं खप हो जाती है।

पेयजल सेवाओं का उपयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत अन्य आसियान देशों की तुलना में कंबोडिया, लाओ पीडीआर और म्यांमार में कम है, जबकि बेहतर पाइप जल आपूर्ति की उपलब्धता के मामले में यह अनुपात और भी कम है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में भी काफी असमानता है। म्यांमार में पाइप्ड सीवेज सुविधा कुल जनसंख्या के केवल 1% से भी कम आबादी को उपलब्ध है, जबकि लाओ पीडीआर में यह 1.1% आबादी के लिए उपलब्ध है। कंबोडिया इस मामले में 14.3% आबादी के साथ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है।

सीएलएमवी में बुनियादी ढांचागत वित्तपोषण

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार, सीएलएमवी सहित आसियान देशों में वार्षिक बुनियादी ढांचागत अंतर लगभग 184 बिलियन यूएस डॉलर का है। बजटीय बाधाओं के कारण, घरेलू संसाधन अकेले इन देशों में विद्यमान ढांचागत वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक प्रभावी वित्तपोषण पद्धति हो सकती है। सीएलएमवी देशों में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निजी निवेश की भी बहुत आवश्यकता और अवसर हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, विशेष रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व वाले बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उद्योगों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के कुछ अभिनव तरीके हैं।

निजी क्षेत्र से सीएलएमवी क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए, पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं ऐसी हों जो बैंकों को स्वीकार्य हों, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक हों। इसके लिए परियोजना के डिजाइन के प्रारंभिक चरण से परियोजना के पूरा होने तक अधिक परियोजना तैयारी सुविधाओं की जरूरत है। सीएलएमवी देशों को मांग और आपूर्ति के बीच के इस अंतर को कम करने के लिए मौजूदा प्रतिभागियों द्वारा बेहतर विनियामक परिवेश में बेहतर प्रदर्शन करना भी जरूरी है।

बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में भारत और सीएलएमवी सहयोग

सीएलएमवी और भारत के बीच कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता का विषय है। "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" को बढ़ावा देने और दक्षिण पूर्वी एशियाई बाजारों से जुड़ने के लिए, भारत सरकार की डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के साथ-साथ सड़क, जल और हवाई परिवहन संबंधी कई संपर्क परियोजनाएं हैं।

मौजूदा सड़क संपर्क परियोजनाओं में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटीपी) और भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। केएमएमटीटीपी से माल के कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक सस्ती दरों पर पहुंच सकेगा और इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव भी कम होगा। इस प्रकार केएमएमटीटीपी का भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास में अहम योगदान होगा। किसी वैकल्पिक मार्ग के अभाव में इस परियोजना के विकास से न केवल भारत के आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक हित पूरे होंगे, बल्कि यह परियोजना भारत के आर्थिक एकीकरण के साथ-साथ म्यांमार के विकास में भी सहायक होगी।

आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग 1360 किलोमीटर लंबी प्रमुख सड़क परियोजना है, जो भारत, म्यांमार और मोरेह (भारत) के जरिए थाईलैंड, बैगान (म्यांमार) और माई सोत (थाईलैंड) को जोड़ती है। भारत, म्यांमार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के दो खंडों का निर्माण कर रहा है, जिनके नाम हैं, 120.74 किमी लंबा केलवा-यज्ञ सड़क खंड; और 69 पुलों सहित 149.70 किमी लंबा तमू-कायगोन-कालवा सड़क खंड।

भारत-सीएलएमवी व्यापार और निवेश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भौतिक कनेक्टिविटी के साथ-साथ डिजिटल कनेक्टिविटी भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। विशेष रूप से वर्तमान कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में यह और भी अहम हो जाती है। संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, म्यांमार ने भारत सहित कई देशों के साथ सीमा पार फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है, जो देश में संपर्क समाधान प्रदान करता है।

भारत ने भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 2015 में आसियान देशों को 1 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण- व्यवस्था की घोषणा की थी। इस उप-क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सीएलएमवी देशों को 40 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान भी दिया गया था। सीएलएमवी देशों में विनिर्माण केंद्र विकसित करने के लिए 77 मिलियन यूएस डॉलर की राशि के साथ परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) भी बनाई गई है, जिसका उपयोग भारत और आसियान के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। भारतीय पावर ग्रिड और म्यांमार ग्रिड के बीच उच्च क्षमता उच्च वोल्टेज ग्रिड इंटरकनेक्शन स्थापित करने के लिए भारत, म्यांमार के साथ वार्ता कर रहा है। भारत सीएलएमवी देशों में डिजिटल गांव की अवधारणा को साकार करने की योजना भी बना रहा है, जिसमें स्थायी प्रौद्योगिकियों और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करना शामिल है।

भारत और सीएलएमवी: इन्फ्रास्ट्रक्चर में सहयोग के नए क्षेत्र

हाल के समय में इस महामारी के साथ-साथ यूएस-चीन व्यापार युद्ध, वैश्विक मंदी और उससे जुड़ी अनिश्चितताओं सहित, विभिन्न घटनाओं के कारण, चीन और अन्य देशों से विभिन्न निवेश दूसरे देशों में स्थानांतरित हो रहे हैं। ये निवेश ज्यादातर अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में किए जा रहे हैं। सीएलएमवी देशों के साथ-साथ भारत को इन निवेशों के लिए आकर्षक वैकल्पिक स्थलों के रूप में चिह्नित गया है। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए, भारत और सीएलएमवी देशों को अपने नागरिकों के कौशल उन्नयन के साथ-साथ अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे और विशेष रूप से कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे तथा रसद सेवाओं का उन्नयन करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा क्षेत्र और जल प्रबंधन में सहयोग

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत का अनुभव सीएलएमवी देशों के सतत विकास के प्रयासों के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण हो सकता है। सीएलएमवी देशों की सरकारों ने कई निवेश प्रोत्साहन जारी कर अक्षय ऊर्जा की ओर रुख किया है। सीएलएमवी देशों में ऊर्जा की भारी मांग और मौजूदा मांग तथा आपूर्ति में अंतर, भारतीय निवेशकों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, भारत और सीएलएमवी देश स्वच्छ पेयजल की समान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विकास और जल प्रबंधन में सहयोग कर सकते हैं। यह सहयोग जल आपूर्ति; सिंचाई; तूफान जल प्रबंधन, बाढ़ प्रबंधन, जल प्रदूषण प्रबंधन और स्वच्छता प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हो सकता है।

ई-कॉमर्स और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोग

उद्योग 4.0 के युग में, तकनीकी ज्ञान और डिजिटल कौशल सीएलएमवी देशों की सम्पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। भारत और सीएलएमवी में बड़ी संख्या में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के होने से ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, टेली-मेडिसिन, वित्तीय सेवाएं और दूरसंचार, परामर्शी और मीडिया एवं मनोरंजन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश के लिए बड़े अवसर हैं। सीएलएमवी देश और भारत विशेष रूप से इंटरनेट कवरेज और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में निवेश कर डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी मिलकर काम कर सकते हैं।

भौतिक संपर्क नेटवर्क विकास में सहयोग

यद्यपि भारत ने आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग और केएमएमटीटीपी को लागू करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, तथापि सीएलएमवी और भारत के बीच समुद्री एवं हवाई संपर्क को बढ़ाने और कनेक्टिविटी कॉरिडोर को आर्थिक कॉरिडोर में बदलने पर वार्ता जारी है। मौजूदा परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान तत्काल आधार पर करने की आवश्यकता है। आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग निर्माण और केएमएमटीटीपी के पहले 2020-21 तक पूरा होने की उम्मीद थी, किन्तु वर्तमान महामारी के कारण इसमें कुछ देरी की आशंका है। इसके पूरा हो जाने के बाद भारत और इस क्षेत्र के बीच संपर्क बढ़ जाएगा। आईएमटी त्रिपक्षीय राजमार्ग का अन्य सीएलएमवी देशों तक विस्तार भी दोनों क्षेत्रों के लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड मोटर वाहन समझौते के प्रस्तावित प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने पर सहमति बन गई है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाली सड़कों के साथ-साथ यात्री तथा व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।

भारत और सीएलएमवी देशों के बीच एकीकरण तथा सहयोग को बढ़ावा देना, इन देशों के बीच विभिन्न परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। भारत और सीएलएमवी देशों के बीच हस्ताक्षरित परियोजना विकास निधि का प्रभावी उपयोग इस क्षेत्र में भारतीय निवेश को और अधिक सुगम बना सकता है।

छठे भारत-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव के दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन का विमोचन

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय निर्यात-आयात बैंक के साथ मिलकर 03-04 दिसंबर, 2020 के दौरान छठे इंडिया-सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव का आयोजन कोविड-19 महामारी के चलते पहली बार ऑनलाइन माध्यम से वर्चुअल प्लैटफॉर्म पर किया गया। इस कॉन्क्लेव में सीएलएमवी और भारत से ऐसे गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जो दोनों क्षेत्रों के बीच भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने भारत-सीएलएमवी की लंबे समय से चली आ रही भागीदारी की बात की और अपने-अपने देशों में विभिन्न क्षेत्रों में इस सहयोग को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र के दौरान इंडिया एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन "इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: भारत के लिए अवसर" का विमोचन किया गया। इस दौरान भारत के माननीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव डॉ. गुरु प्रसाद महापात्र, कम्बोडिया के वाणिज्य मंत्रालय के माननीय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री चुओन दारा, वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्रालय के उप मंत्री श्री काओ क्युओक हंग, लाओ पीडीआर की माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुश्री खेमानी फोल्सेना, म्यांमार के माननीय वाणिज्य मंत्री डॉ. थान माइंत, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष तथा कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक श्री उदय कोटक और सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बनर्जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ■

चुनिंदा विनिर्माण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करना

आर्थिक वृद्धि और विकास में विनिर्माण क्षेत्र की अहम भूमिका होती है। कमजोर विनिर्माण क्षेत्र अक्सर उच्च आयात निर्भरता और बड़े व्यापार घाटे में तब्दील हो जाता है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र का हालिया प्रदर्शन सुस्त रफ्तार का संकेत है। देश में मजबूत और बढ़ती निजी खपत की मांग के बावजूद भारत के सकल मूल्य योजन में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 2019-20 में घटकर 15.1% हो गई, जबकि 2010-11 में यह 18.4% थी। विनिर्माण में यह संकुचन देश में निजी खपत में मजबूत वृद्धि के बावजूद है, जिसमें 2011-12 से 2019-20 के दौरान 12.7% की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की गई।

घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट का असर यह हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ गई है। अंतिम उपयोग (पूंजी, मध्यवर्ती और उपभोक्ता वस्तुओं) के लिहाज से भारत के आयातों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019 में भारत द्वारा किए गए आयातों का लगभग 79% हिस्सा मध्यवर्ती वस्तुओं का रहा, जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र की आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्भरता को दर्शाता है। विनिर्माण क्षेत्र में आयातों का अधिक होना भी भारत के विनिर्माण निर्यातों (27.3%) में विदेशी मूल्य वर्धित सामग्री के उच्च स्तर में तब्दील होता है। नतीजतन, बुनियादी धातुओं, निर्मित धातु उत्पादों, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों, विद्युत उपकरणों, और मशीनरी एवं उपकरणों के मामले में निर्यातों की आयात तीव्रता विशेष रूप से अधिक है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा हाल ही में एक शोध अध्ययन किया गया, "आत्मनिर्भर भारतः दृष्टिकोण और रणनीतिक क्षेत्र"। इस शोध अध्ययन में आयातों को कम करने के लिए कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, रसायन एवं संबद्ध क्षेत्र, दवाएं और चुनिंदा कृषि उत्पाद जैसे घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया गया है। अध्ययन में ऑटो पुर्जे, लौह और इस्पात जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जहां भारत के लिए कुल व्यापार अधिशेष है, तथापि कुछ उप-श्रेणियों में, विशेष रूप से चीन के साथ व्यापार घाटा है। इसके अलावा, अध्ययन में आयात के विकल्पों के रूप में दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, क्योंकि हाई-टेक विनिर्माण में प्रवेश करने के लिए इन रणनीतिक खनिजों को संरक्षित करना भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। भारत द्वारा इन क्षेत्रों से 186 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का आयात किया जाता है, जिसमें भारत द्वारा कुल आयातों के लगभग 39 प्रतिशत और गैर-तेल आयातों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी इसी क्षेत्र की है।

प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के विश्लेषण के आधार पर, अध्ययन में घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न सेक्टर-विशिष्ट रणनीतियों की सिफारिश की गई है। उदाहरण के लिए, जहां कृषि और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे क्षेत्रों में, रणनीति बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता बताई गई है, ताकि सहयोगपूर्ण व्यवस्था बनाई जा सके और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य भागीदार देशों में जावक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं गहन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ऐसी रणनीतियां बनाने पर फोकस किया गया है, जिससे आयात निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अध्ययन में सुझाई गई कुछ अन्य रणनीतियों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैंः नवाचार आधारित विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के विशिष्ट उपाय करना, कर और शुल्क की ढांचागत खामियों को दूर करना, संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करना, और सरकारी विनियमों एवं कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन करना।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन में कुछ बहुआयामी रणनीतियों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो पूरे विनिर्माण क्षेत्र में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित कर सकती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियां हैंः

- **विदेशी निवेश आकर्षित करना:** सरकार ने विनिर्माण और निर्यातों को बढ़ाने के लिए निवेश को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की हैं। तथापि, एक सुदृढ़ निवेश तंत्र विकसित करना महत्त्वपूर्ण है, जिसके जरिए अग्रणी वैश्विक फर्मों को भारत में अपने परिचालनों में निवेश करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए डब्ल्यूटीओ के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट निवेश संवर्धन रणनीतियों सहित एक केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक होगा। उचित प्रोत्साहनों के माध्यम से अधिक से अधिक निवेश को लक्षित करने के लिए अक्षय ऊर्जा, खाद्य और पेय पदार्थ, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, जिनमें अन्य के साथ-साथ उत्पादन और पूंजी निवेश प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रोत्साहन, करों में छूट, पूंजी निवेश पर ब्याज छूट शामिल हो सकती है।

- **सार्वजनिक खरीद का लाभ:** सार्वजनिक खरीद भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 20-30% है, जो सरकार को विनिर्माण कंपनियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण क्रेता बनाता है। भारत को यूरोपीय संघ द्वारा लागू "मूल्य-गुणवत्ता अनुपात" के अनुरूप अपने खरीद (प्रोक्योरमेंट) दिशानिर्देशों में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। सरकार प्रक्रियाओं को एमएसएमई के लिए अधिक अनुकूल बनाने पर भी विचार कर सकती है। इस संबंध में, सरकार बड़े खरीद कॉन्ट्रैक्टों को छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्टों में विभाजित करने पर विचार कर सकती है। सार्वजनिक खरीद के लिए एक अलग कानून लागू करने की भी जरूरत है, क्योंकि केंद्रीय खरीद कानून के अभाव में अस्पष्टता और प्रक्रियात्मक देरी हो जाती है।

- **राज्यों की भूमिका:** यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के संघीय ढांचे में राज्यों को निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी निवेश नीतियां और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहन योजनाएं निर्धारित करने का अधिकार है। इसलिए, राज्य सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए ठोस प्रोत्साहन संरचना तैयार करने के साथ-साथ राज्यों में "व्यवसाय सुगमता" में सुधार लाने की दिशा में सक्रिय रहें।

- **मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करना:** घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को कुछ मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। यदि किसी देश से आयात बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में सरकार एफटीए के भागीदार विकासशील देशों के लिए कुछ रियायत पर "ग्रैजुएशन क्लॉज", "सनसेट क्लॉज" और "ट्रिगर मैकेनिज्म" लागू करने पर विचार कर सकती है।

- **नवाचार तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना:** विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए यह भारत के लिए परिवर्तनकारी उपाय हो सकता है। अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस पर किए गए व्यय पर आयकर में अधिक छूट देने जैसे अन्य उपयुक्त नीतिगत उपाय करने के साथ-साथ अनुसंधान एवं विकास के लिए फंड आवंटन में भी वृद्धि की जा सकती है। सरकार कनाडा जैसे देशों द्वारा प्रदान किए जा रहे दोहरे टैक्स क्रेडिट अलाउंस सिस्टम पर विचार कर सकती है, जिसमें अनुसंधान और विकास में खर्च के स्तर के साथ-साथ वृद्धिशील खर्च के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार घरेलू कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 22% की कम कॉर्पोरेट टैक्स दर के अलावा धारा 35 (2एबी) के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास पर कर में छूट देने पर भी विचार कर सकती है।

- **औद्योगिक क्लस्टरों में क्षमता निर्माण:** देश में मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, इन समूहों के प्रदर्शन का आकलन करने, मौजूदा क्लस्टरों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और नए क्लस्टरों के विकास के लिए क्षेत्रों/उपक्षेत्रों को चिह्नित करने हेतु एक तंत्र विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य स्तरीय सहायता और सहयोग की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिकांश क्लस्टर राज्य स्तरीय पहलों के माध्यम से विकसित किए जाते हैं। केंद्र सरकार "मार्केट एक्सिस इनिशिएटिव स्कीम" के तहत वित्तीय सहायता के माध्यम से इन क्लस्टरों का आकलन करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर सकती है। क्लस्टरों का मूल्यांकन कर संबंधित क्षमता निर्माण गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। राज्य सरकारें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ भी उठा सकती हैं।

- **व्यवसाय सुगमता में सुधार लाना:** भारत ने व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़े सुधार किए हैं, जिससे देश में निवेश परिवेश में सुधार हुआ है। हालांकि, देश अब भी कॉन्ट्रैक्टों को लागू करने और संपत्ति रजिस्टर करने जैसे क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से पीछे है। इसलिए देश में व्यवसाय के लिए परिवेश को और बेहतर बनाने के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन और भूमि अधिग्रहण को आसान बनाना महत्त्वपूर्ण होगा। देश में वाणिज्यिक विवादों के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में भी फेरबदल करने की जरूरत है। विशेष रूप से न्यायपालिका में निचले स्तर पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा। देश में मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्रों का विस्तार करने और विशेष वाणिज्यिक अदालतों के माध्यम से न्यायिक क्षमता बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

- **कौशल विकास:** सरकार और अग्रणी संगठनों द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक संस्थानों में क्षेत्र-विशिष्ट विशेषीकृत केंद्र बनाने में निवेश कर किया जा सकता है। इस रणनीति को लागू करने में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और राज्य स्तरीय कौशल विकास परिषदों की अहम भूमिका होगी। इसके अलावा, उच्च और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अलग से एक कोष बनाया जा सकता है।

'आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतियां" विषय पर वेबिनार

"आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीतियां" विषय पर 16 सितंबर, 2020 को कार्यकारी आलेख का विमोचन। इसका विमोचन श्री के राजारमन, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया।

भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

परिचय

भारत में, हाल के वर्षों में, अक्षय (नवीकरणीय) ऊर्जा ग्रिड विद्युत को बढ़ाने, ऊर्जा को सुलभ बनाने, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने और भारत को अपने कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करने में तेजी से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। थर्मल ऊर्जा के बाद यह ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

अक्षय ऊर्जा के लिए भारत की वर्तमान स्थापित क्षमता 2003-04 में 3.9 गीगावाट से बढ़कर सितंबर, 2020 में लगभग 89.2 गीगावाट हो गई है। 30 सितंबर, 2020 तक, 89.2 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता में से सौर और पवन ऊर्जा का हिस्सा क्रमशः 36.1 गीगावाट और 38.1 गीगावाट रहा। बायोमास और लघु जल विद्युत का हिस्सा क्रमशः 10.1 गीगावाट और 4.7 गीगावाट है। अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत स्थापित क्षमता में 15.3 गीगावाट के योगदान के साथ, देश में कर्नाटक का सबसे अधिक योगदान रहा। इसके बाद 14.7 गीगावाट और 11.3 गीगावाट के साथ क्रमशः तमिलनाडु और गुजरात का स्थान रहा।

उद्योग आकलनों के अनुसार, भारत में 100 मीटर की हब ऊंचाई पर पवन ऊर्जा क्षेत्र में 300 गीगावाट से अधिक की क्षमता है; यदि यह मान लिया जाए कि बंजर भूमि का 3% भी सौर ऊर्जा के लिए उपलब्ध कराया जाए तो लगभग 750 गीगावाट की सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है; लगभग 20 गीगावाट की लघु जल विद्युत और लगभग 25 गीगावाट की जैव ऊर्जा उत्पादन क्षमता है।

जल विद्युत उत्पादन के मामले में भारत जापान से आगे निकल गया है और 50 गीगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक राष्ट्र बन गया है। अंतरराष्ट्रीय जल विद्युत संघ (आईएचए) के अनुसार भारत से आगे अब केवल कनाडा, अमेरिका, ब्राजील और चीन हैं। मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अक्षय विद्युत उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट दर्ज की गई। 2019-20 के दौरान, इस उद्योग के शुद्ध लाभ मार्जिन में लगातार दूसरे साल 4.8% अंकों से 9.6% तक की गिरावट आई।

लाभप्रदताः अक्षय ऊर्जा

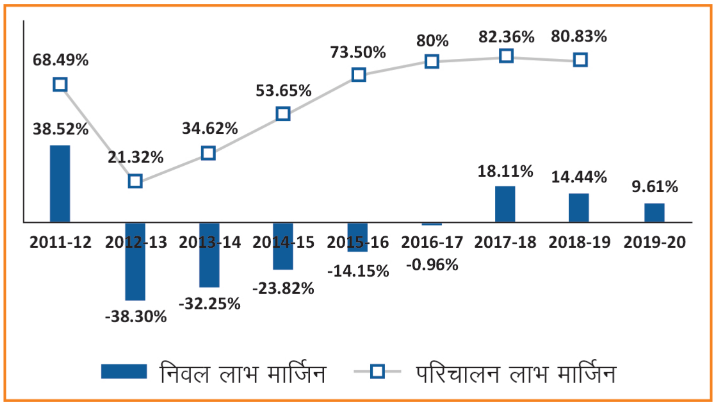

स्रोतः सीएमआईई इकनॉमिक आउटलुक

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अध्यधीन, अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं के लिए ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। अप्रैल 2009 से अगस्त 2020 के दौरान, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 123 परियोजनाओं के लिए 38.59 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो प्रति परियोजना औसतन 313.8 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। यदि देशवार एफडीआई की बात करें तो 31 परियोजनाओं के माध्यम से 8.1 अरब यूएस डॉलर का सबसे अधिक निवेश यूएसए से मिला। इसके बाद चीन का स्थान रहा, जिसने 11 परियोजनाओं में 7.7 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया। वहीं, यूके ने 8 परियोजनाओं के जरिए 4.4 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया।

कोविड का प्रभाव और अन्य चुनौतियां

पवन ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष टैरिफ में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। ये टैरिफ वित्तीय वर्ष 2018 की 2.6 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में 2.8 रुपये प्रति यूनिट हो गई। क्रिसिल रिसर्च के अनुसार, पवन ऊर्जा कुछ राज्यों तक ही सीमित है, इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर भी कंजेस्टेड होता है और इस क्षेत्र पर नकारात्मक असर पड़ता है। राज्यों की वितरण कंपनियों की कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल और भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड, मॉड्यूलों के आयात के लिए चीन पर निर्भरता और बढ़ती समानुपातिक ग्रिड बैलेंसिंग लागत इस क्षेत्र के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं। क्रिसिल रिसर्च के अनुसार, राज्य वितरण कंपनियों से भुगतान में देरी एक बड़ी चिंता का विषय है। राज्य वितरण कंपनियों द्वारा अतिदेय (ऐसे बिल जो 60 दिनों से अधिक समय से चुकाए नहीं गए हैं) वित्तीय वर्ष 20 के अंत तक ₹10,500 करोड़ तक पहुंच गया। समग्र निजी क्षमता में एनटीपीसी, एसईसीआई और पीटीसी जैसे विश्वसनीय केंद्रीय काउंटर पार्टियों को मार्च 2022 तक 29% तक एक्सपोजर का बढ़ना अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए आशा की किरण है।

कोविड 19 महामारी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र को काफी प्रभावित किया है, जो भारतीय सौर उद्योग में निवेश में आई कमी में परिलक्षित होता है। यह गिरावट मुख्य रूप से पहली तिमाही के दौरान सौर प्रतिष्ठानों में मंदी और विनिर्माण इकाइयों में नए निवेश की कमी के कारण देखी गई। तालाबंदी वाले चरण के दौरान विद्युत क्षेत्र की मांग में गिरावट देखी गई और कम संग्रह तथा धीमी रिकवरी के साथ मांग में इस गिरावट का प्रतिकूल असर वितरण कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का पूर्वानुमान है, जो पहले से दबावग्रस्त हैं। नियामक वातावरण अनुकूल बना रहा, जो कोविड महामारी के बीच सापेक्ष नकदी प्रवाह स्थिरता के लिए एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। ■

चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातों के लिए घरेलू बाधाएं

इंडिया एक्ज़िम बैक ने हाल ही में "चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातों के लिए घरेलू बाधाएं" विषयक एक शोध अध्ययन किया है। इसमें चुनिंदा क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली घरेलू नीतिगत बाधाओं का विश्लेषण किया गया है। इनमें टेक्सटाइल्स व अपैरल, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल और ऑटो-पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स (मोबाइल फोनों पर फोकस) और फार्मासूटिकल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस अध्ययन का विमोचन "चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातों में नीतिगत बाधाओं को दूर करने की रणनीतियां" विषय पर 3 अक्टूबर, 2020 को आयोजित चर्चापरक वेबिनार के दौरान भारत के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया।

चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातों में नीतिगत बाधाओं को दूर करने की रणनीतियां

चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यातों में नीतिगत बाधाओं को दूर करने की रणनीतियां विषय पर 3 अक्टूबर, 2020 को आयोजित चर्चापरक वेबिनार के दौरान भारत के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल

अध्ययन के अनुसार, भारत सरकार निर्यातों के संवर्धन और बेहतर परिचालन परिवेश बनाने के लिए नीतियां बना रही है। किन्तु इसके साथ-साथ उन बाधाओं को दूर करने पर फोकस करने की भी जरूरत है, जिनके चलते इन नीतियों का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। अध्ययन में उन विषयों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में निर्यातकों को गुजरना पड़ता है। इनमें अन्य के साथ-साथ बंदरगाहों पर लागत कम करने के लिए सरकार का सीधा हस्तक्षेप करने; विशेष रूप से, "भारत से वस्तु निर्यात योजना" (एमईआईएस) के खत्म होने के बाद कोई उत्पादन उन्मुख आकर्षक प्रोत्साहन योजना लाने; सरकार द्वारा मंजूरियों और रिफंड तथा कस्टम मंजूरी में लगने वाले समय को कम करने तथा विनिर्माण उद्योग में सुधार के लिए जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड में तेजी लाने की जरूरत जैसे उपाय शामिल हैं। अध्ययन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि यदि जीएसटी रिफंड त्वरित आधार पर हो तो जीडीपी 2 प्रतिशत, निर्यात 7 प्रतिशत, कुल आयात 6 प्रतिशत और रोजगार करीब 4 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं।

अध्ययन में इन चिह्नित क्षेत्रों पर फोकस करने के लिए कुछ विशिष्ट प्राथमिक क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें काम किया जाए तो निर्यातकों की परिचालनगत क्षमता में तेजी से सुधार आ सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

टेक्सटाइल और अपैरल क्षेत्र

- वस्त्र क्षेत्र में आयातक सामग्री के सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य पर शुल्क का भुगतान करते हैं, जिसमें समुद्री ढुलाई भाड़ा भी शामिल होता है। इसके बाद आयातक समुद्री भाड़े पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत फिर से जीएसटी का भुगतान करते हैं और सरकार को कर देते हैं। इस तरह समुद्री भाड़े पर दोहरा कराधान है, जिसमें आरसीएम के तहत जीएसटी के भुगतान से छूट मिल सकती है। इसके अलावा, पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन में एक समान जीएसटी लगाया जा सकता है।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को जारी रखने और इसके अंतर्गत आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता है। एटीयूएफएस में कताई खंड को शामिल करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस उद्योग को पूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए, एटीयूएफएस में निम्नलिखित संशोधन करने की भी आवश्यकता है: (क) एकल इकाई के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) की सीमा बढ़ाना, (ख) प्रति इकाई सीआईएस का प्रतिशत बढ़ाना, और (ग) स्थापित मशीनरी के उपयोग की जांच करना और निरीक्षण में तेजी लाना, जिसमें वर्तमान में लंबा समय लगता है। साथ ही, ईपीसीजी योजना के खत्म होने के बाद, इस उद्योग के आधुनिकीकरण को सुगम बनाने के लिए एटीयूएफएस के तहत सीआईएस के लिए पात्र मशीनों के लिए आयात शुल्क समाप्त करना चाहिए।
- एमईआईएस के स्थान पर 7 मार्च, 2019 से शुरू की गई राज्य और केंद्रीय लेवी तथा करों में छूट योजना (आरओएससीटीएल) में धागे या कपड़े को शामिल नहीं किया गया। इन उत्पादों को राज्य और केंद्रीय शुल्कों तथा करों में छूट नहीं मिलती है और अध्ययन में कहा गया है कि इसकी भरपाई करने के लिए निर्यात उत्पादों पर कर अथवा शुल्क में छूट योजना (आरओडीटीईपी) के तहत मिलने वाले लाभ धागे और कपड़े के निर्यातों के लिए उपलब्ध कराए जाएं।
- वैश्विक मानदंडों को पूरा करने वाली गुणवत्ता हासिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए खास तौर पर बिजली टैरिफ सब्सिडी, श्रम कानूनों, निरीक्षणों आदि के संबंध में एसएमई और बड़ी इकाइयों के बीच कृत्रिम भेद को दूर करने की जरूरत है। साथ ही, इस स्तर पर हासिल करने के लिए बुनाई, प्रसंस्करण, मेड-अप और गारमेंट इकाइयों के समेकन के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

रत्न और आभूषण

- भारतीय हीरा उद्योग पर लैब में विकसित हीरे का प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके लिए सरकार प्राकृतिक हीरे के लिए प्रामाणिकता के उद्योग प्रमाण पत्र को सहयोग प्रदान करने पर विचार कर सकती है, ताकि इस उद्योग को उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके।
- वर्तमान में, भारतीय बैंक अनगढ़ हीरे के आयात के लिए गारंटी सपोर्ट देने से परहेज करते हैं। परिणामस्वरूप, निर्यातकों की निर्भरता आपूर्तिकर्ता ऋण पर बढ़ रही है। कच्चे माल की खरीद को कम करने के लिए सरकार एक फंड बनाने में उद्योग संघ की सहायता करने पर विचार कर सकती है, जिससे ऋण तक पहुंच आसान हो सके। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए बैंक ऋण शर्तों को भी थोड़ा आसान बनाने की जरूरत है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो पुर्जे

- देश में ऑटोमोटिव उद्योग इस समय सबसे बड़े करदाताओं में से एक है। भारत में इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) आधारित वाहनों के लिए वर्तमान में 28% की उच्चतम जीएसटी दर है। इसके अलावा, 1-22% तक क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया जाता है। इससे भारत में वाहन सबसे अधिक कर वाले विनिर्मित उत्पादों में शामिल हो जाते हैं। इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जीएसटी की मौजूदा दरों को नीचे लाने की जरूरत है।
- ऑटो पुर्जे उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि विनियामक और तकनीकी परिवर्तनों के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है: क) उत्सर्जन; ख) सुरक्षा; ग) उद्योग 4.0; घ) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी; ई) वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग को बढ़ाना। इसलिए इस उद्योग में प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत है। इसके अलावा, सरकार को आगामी तकनीकी बदलावों (जैसे बिजली ट्रेनों के विद्युतीकरण) को लक्षित करते हुए विशिष्ट प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष स्थापित करने पर विचार करने की आवश्यकता है। ये फंड सॉफ्ट लोन, कर प्रोत्साहन आदि के रूप में सहयोग दे सकते हैं।
- भारत में स्टील जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण कच्चे माल की लागत बहुत अधिक है, जो इस उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। लागत के दबाव को कम करने के लिए, सरकार एचआर/सीआर स्टील के साथ-साथ एलॉय स्टील्स जैसी सामग्री पर सीमा शुल्क को कम करने पर विचार कर सकती है ।
- भारतीय ऑटोमोबाइल के लिए बाजार को और बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार समझौतों का प्रस्ताव रखने और पारस्परिक टैरिफ में कटौती की संभावनाएं तलाशने की भी आवश्यकता है।

मोबाइलों पर फोकस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स

- घरेलू और विदेशी दोनों फर्मों से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार द्वारा सहायता के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार करने की आवश्यकता है:
    - वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करना;
    - पूर्वव्यापी प्रभावों के साथ सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में परिवर्तन से बचना;
    - कराधान में अस्पष्टता को दूर करना;
    - उन वस्तुओं की जांच करना जिन पर जीएसटी रिफंड नहीं किया जाता है, भले ही वे गतिविधियां निर्यात के लिए महत्त्वपूर्ण हों;
    - एकाधिक अनुमोदनों के लिए एक वास्तविक सिंगल विंडो बनाना; और
    - पर्यावरण संबंधी शर्तों को पूरा करना, ई-कचरा प्रबंधन जैसी अधिसूचित विनियामकीय आवश्यकताओं को लागू करने की व्यावहारिकता का आकलन करना।
- अध्ययन में पाया गया है कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों को कार्यशील पूंजी (ब्याज अनुदान), ऋण गारंटी, कामगारों के प्रशिक्षण के लिए सहायता, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और डिजाइन एवं सप्लाई चेन/क्लस्टरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। साथ ही ऋणों तक आसान पहुंच होना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, घरेलू क्षमता और सामग्री में सुधार करने के लिए मोबाइल फर्मों के लिए अलग राष्ट्रीय डिजाइन इकोसिस्टम बनाना और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना में सुधार करने भी पर विचार किया जा सकता है।
- जीवीसी में इन्वेंट्री प्लानिंग और परिचालन लागत (कार्यशील पूंजी) के महत्त्व को समझना अत्यावश्यक है। इस संबंध में, ऐसी नीतियों या कार्यों से बचने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए जो इन्वेंट्री योजना में बाधा डालते हैं और/या कार्यशील पूंजी की लागत बढ़ाते हैं। इसके अलावा, जीवीसी को सुगम बनाने के लिए मंत्रालयों/विभागों के बीच समन्वय की भी आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में, जीवीसी को सुगम बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है।

फार्मासूटिकल्स

- फार्मासूटिकल्स क्षेत्र को अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) में वृद्धिशील रूप से निवेश करने की जरूरत है। इसलिए, व्यवसाय सुगमता, व्यापार सुगमीकरण, मानव संसाधन विकास, संस्थागत लिंकेज और कराधान के लिए अनुकूल नीतियों की आवश्यकता है।
- बायो-फार्मासूटिकल उप-क्षेत्र भविष्य के लिए एक आशाजनक अवसर है, और भारत इस उप-क्षेत्र में अपने विभिन्न प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकता है। इसके लिए अध्ययन में बायो-फार्मासूटिकल्स के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने की संस्तुति भी की गई है।
- गवर्नेंस की बात करें तो यह क्षेत्र विभिन्न एजेंसियों और विभागों की मौजूदगी से गंभीर रूप से प्रभावित होता है, जिससे इस क्षेत्र में वृद्धि की गति धीमी पड़ जाती है। इसके अलावा, मूल्य नियंत्रण इस क्षेत्र के विकास में अवरोधक साबित हुआ है और इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। इस संबंध में, इस क्षेत्र के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रणाली के माध्यम से नियामकीय सुगमीकरण पर विचार किया जा सकता है।
- एफटीए जैसी संस्थागत प्रणाली के माध्यम से प्रमुख बाजारों में प्रवेश करने में आने वाले अवरोधों से निपटने की जरूरत है। इसके अलावा, विनियमित बाजारों में पैठ बनाने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए वैश्विक स्तर पर नियामकीय अपेक्षाओं पूरी करने के साथ-साथ भारतीय उत्पादों के मानकों को उच्चतम स्तर तक बढ़ाने की भी जरूरत है। ■

दुर्लभ मृदा तत्त्व

दुर्लभ मृदा तत्त्व 17 धात्विक तत्त्वों का समुच्चय होते हैं। इनमें आवधिक टेबल में 15 लैन्थेलाइड और स्कैन्डियम और इट्रीयम भी शामिल होते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व मूल रूप धातुएं होती हैं, इसलिए इन्हें प्रायः दुर्लभ मृदा धातुएं भी कह दिया जाता है। तथापि, आर्थिक दोहन के लिए इन धातुओं का खनन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें अलग से खोज पाना अपने आप में असाधारण काम है।

इस प्रकार के दुर्लभ तत्त्वों का संरक्षण करना और इनकी उपलब्धता बनाए रखना देश की दीर्घकालिक सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह भी उल्लेखनीय है कि अक्षय ऊर्जा सहित रक्षा, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योगों में उत्पादों के विनिर्माण के लिए इन दुर्लभ मृदा तत्त्वों पर काफी अधिक निर्भरता होती है।

यूनाइडेट स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार, दुर्लभ मृदा तत्त्वों का वैश्विक भंडार 2018 में 120 एमटी आंका गया था। इस 120 एमटी के भंडार में से 37% हिस्सा अकेले चीन में है। इसके बाद ब्राजील और वियतनाम का स्थान आता है, जिनका हिस्सा 18-18% है।

वैश्विक दुर्लभ मृदा भंडार

देश	वैश्विक दुर्लभ मृदा भंडार ('000 टन में)	वैश्विक भंडार में हिस्सा (%)
चीन	44,000	36.7%
ब्राजील	22,000	18.3%
वियतनाम	22,000	18.3%
रूस	12,000	10.0%
भारत	6,900	5.8%
ऑस्ट्रेलिया	3,300	2.8%
ग्रीनलैंड	1,500	1.3%
यूएसए	1,400	1.2%
तंज़ानिया	890	0.7%
कनाडा	830	0.7%
दक्षिण अफ्रीका	790	0.7%
अन्य देश	4,080	3.7%
वैश्विक योग (पूर्णांक में)	**1,20,000**	**100%**

स्रोतः यूएसजीएस; इंडिया एक्ज़िम बैंक शोध

दुर्लभ मृदा का कुल वैश्विक उत्पादन 2018 में 170,000 टन दर्ज किया गया था। 1994 में यह उत्पादन 64,000 टन था। जाहिर है, दो दशकों के दौरान इसमें अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है और सालाना 40.5% की औसत वृद्धि दर्ज की गई। दुर्लभ मृदा तत्त्वों के उत्पादन में चीन का हिस्सा 1994 के 47.4% से बढ़कर 2010 में 97.7% तक पहुंच गया था, जो 2018 में गिरकर 70.6% हो गया।

दुर्लभ मृदा तत्त्वों का वैश्विक निर्यात 2019 में 1,584.2 मिलियन यूएस डॉलर का रहा था, जो 2009 में मात्र 635.8 मिलियन यूएस डॉलर का था। इस अवधि के दौरान इनके निर्यातों में 25.1% की सीएजीआर दर्ज की गई। 2019 में शीर्ष निर्यातकों में चीन (28%); मलेशिया (16%); जापान (14%); वियतनाम (10%); और म्यांमार (9%) शामिल रहे।

जहां तक दुर्लभ मृदा तत्त्वों में भारत के व्यापार की बात है, तो 2019 में भारत से दुर्लभ मृदा तत्त्वों का निर्यात 23.5 मिलियन यूएस डॉलर का रहा, जो 2009 में केवल 0.1 मिलियन यूएस डॉलर का था। इसी अवधि के दौरान, आयात भी 6.8 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 18.3 मिलियन यूएस डॉलर के हो गए। इसके अलावा, जब पिछले कुछ वर्षों से लगातार भारत का व्यापार घाटा दर्ज किया जा रहा था, 2017 के दौरान भारत ने व्यापार अधिशेष (4.4 मिलियन यूएस डॉलर), 2018 में (2.1 मिलियन यूएस डॉलर) और 2019 में (5.2 मिलियन यूएस डॉलर) दर्ज किया।

भारत से दुर्लभ मृदा तत्त्वों के निर्यातों में मूल्य और निर्यात स्थल, दोनों ही मामलों में काफी अनियमितता रही है। यदि किसी ऐसे देश की बात करें, जिसे भारत ने नियमित रूप से निर्यात किया है तो वह जापान है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत से दुर्लभ मृदा तत्त्वों के कुल निर्यातों में जापान का हिस्सा सामान्यतया दोहरे अंकों में रहा है। 2019 में, भारत के लिए वियतनाम 32% हिस्से के साथ सबसे बड़ा आयातक रहा। इसके बाद 28% के साथ जापान का स्थान रहा।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादन और विनिर्माण के प्रयास किए जाते रहे हैं। इस दृष्टि से देश के लिए यह जरूरी है कि दुर्लभ मृदा तत्त्वों के संरक्षण की संभावनाएं वृद्धिशील रूप से तलाशी जाती रहें।

दुर्लभ मृदा तत्त्वों को किसी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा में योगदान देने वाले विभिन्न उद्योगों में एकीकृत किया गया है। इनमें से कुछ खनिज रणनीतिक महत्त्व के होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल रक्षा, ऊर्जा और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र में दुर्लभ तत्त्वों का उपयोग बढ़ने के साथ मौजूदा अंतिम उपयोक्ता क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी इनकी मांग बढ़ रही है। इसलिए दुर्लभ तत्त्वों के प्रयोग, खपत, खनन के साथ-साथ इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार और खनिज सहयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय रणनीति बनाना महत्त्वपूर्ण होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में दुनिया के पांचवें सबसे बड़े दुर्लभ मृदा तत्त्व भंडार हैं। किन्तु, भारतीय कंपनियां घरेलू स्तर पर खनन में निवेश नहीं कर रही हैं। हालांकि वर्तमान में, इनकी मांग आयातों के जरिए, विशेष रूप से चीन से आयातों के जरिए पूरी की जाती है। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दुर्लभ तत्त्वों के निर्यात पर प्रतिबंध हो सकते हैं। इस प्रकार, इस क्षेत्र में निवेशों पर रणनीतिक रूप से विचार करना अत्यावश्यक हो गया है। ■

चीन में बैंक के विस्तार के परिणाम और राजनीतिक उद्भव

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने 2016 में ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की। इस पुरस्कार का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य देशों के नागरिकों द्वारा दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान से अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण जैसे विषयों में डॉक्टोरल शोध को बढ़ावा देना है। यह शोध अध्ययन डॉ. एडम याओ लिउ की "बिल्डिंग मार्केट्स विदिन अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशंसः द पॉलिटिकल इकनॉमी ऑफ बैंकिंग डेवलपमेंट इन चाइना" ("नियंत्रित संस्थाओं में बाजार निर्माणः चीन में बैंकिंग विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था") शीर्षक वाली थीसिस पर आधारित है, जिसे इंडिया एक्ज़िम बैंक के ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक पुरस्कार (ब्रिक्स पुरस्कार) 2020 के लिए चुना गया है। डॉ. लिउ वर्तमान में नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में असिस्टैंट प्रोफेसर हैं। डॉ. लिउ ने अपनी डॉक्टोरल डिग्री स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए से 2018 में प्राप्त की थी।

आर्थिक विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, ज्यादातर विकासशील देशों में वित्तीय सिस्टम विकसित नही हों पाए। इससे भी बदतर स्थिति यह रही कि, ऋण उद्यमशील और उत्पादक लोगों के बजाय प्रायः शक्तिशाली लोगों के लिए ही सुलभ रहा। यह स्थिति विकास में बाधक होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि विकासशील देश वित्तीय विकास को कैसे बढ़ावा दें। समाज विज्ञानियों द्वारा इसका प्रायः दिया जाने वाला समाधान है, सीमित सरकार। उनका कहना है कि कुछ सुदृढ़ राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजार में उन्मुक्त प्रवेश को सुगम बनाने और अभिजात्य वर्ग द्वारा संसाधनों को कब्जा लेने की स्थिति पर लगाम लगाने के लिए राजनीतिक सत्ता, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकप्रिय चुनावों को अलग रखा जाए। सिद्धांततः, सीमित सरकार की परिकल्पना व्यावहारिक रूप से अव्यवहार्य प्रतीत होती है। कोई सरकार अपनी शक्ति को सीमित नहीं करना चाहती है। तथापि, सीमित सरकार के बिना भी शक्तियों को सीमित करने की आशंका मात्र से ही बाजार में गिरावट आ जाती है। आर्थिक विकास के लिए मूलभूत राजनीतिक चुनौती यही है।

हालांकि माओ के बाद भी चीन में अभी तक एक पार्टी का अथॉरिटेरियन शासन है। फिर भी चीन ने पूरी प्रतिस्पर्धा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली बनाई है। सुधारवादी युग में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या तेजी से बढ़ी और कुछ वर्षो के लिए इन बैंकों से प्रमुख रूप से निजी फर्मों को ही ऋण दिया जाता रहा। सीमित सरकार के बिना यह घटना क्या बताती है? इस शोध अध्ययन में इसी जवाब की पड़ताल की गई है, जिसे संगठनात्मक स्पिन-ऑफ कहा गया है। बाजार को पूरी तरह खोलते हुए बीजिंग ने स्थानीय बैंकिंग बाजार को स्थानीय सरकारों के लिए खोल दिया। यह ठीक वैसे ही था, जैसे कोई फर्म आंतरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और फर्म का समग्र रिटर्न बढ़ाने के लिए अपनी सहायक कंपनियां बनाने लगे। नए स्थानीय सरकारी बैंक (एलएसबी) लाभ बढ़ाने वाले बैंकों से थोड़े अलग हैं, उनका संगठनात्मक ढांचा और संगठनात्मक मिशन केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों की तरह बनाए गए। इससे निजी फायनैंसर बाजार के बनने के चरण में अप्रासंगिक हो गए। साथ ही उनके वित्तीय विनियमन की सरकार की चिंता भी खत्म हो गई। समय के साथ निजी और विदेशी बैंक बाजार में पहुंचे तो जरूर, लेकिन केवल सरकार द्वारा बनाए गए बैंकों के शेयरधारक के रूप में।

इस शोध अध्ययन में बताया गया है कि संगठनात्मक स्पिन-ऑफ से चीनी सरकार को बढ़ते बैंकिंग बाजार से काफी लाभ पहुंचा और बाजार पर सरकार का राजनीतिक नियंत्रण बना रहा। परंपरागत विचार के विपरीत, यह अध्ययन बताता है कि संगठनात्मक स्पिन-ऑफ निजी फर्मों के वित्तपोषण में सहायक रहा। इस तर्क के परीक्षण के लिए इस अध्ययन में एथनोग्राफिक और स्टैटिस्टिकल पद्धतियों का उपयोग किया गया है। इसमें शामिल किए गए प्रमुख विचार और हाइपोथीसिस विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित हैं, जिनके लिए छह प्रांतों में 22 महीनों तक फील्डवर्क किया गया। फील्डवर्क के दौरान एक अनूठा डेटासेट तैयार किया गया, जिसमें 1990 के बाद बने तमाम चीनी बैंकों, क्रेडिट यूनियनों और उनकी शाखाओं (N=223,444) की तमाम सूचनाएं जमा की गई। फिर इस डेटा को या तो एक बड़े उद्योग डेटासेट (N=675,657) के साथ मिला दिया गया या उनके साथ मिलाकर संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया गया। 2000-2012 की अवधि को कवर करते हुए निजी फर्मों के छह राष्ट्रीय सर्वेक्षण किए गए, फर्म मैनेजरों का एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया और बैंकरों को शामिल करते हुए एक मौलिक सर्वेक्षण किया गया।

इस परियोजना ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समसामयिक चीनी राजनीति के अध्ययन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही यह कॉन्ट्रैक्ट-गहन बाजार किस तरह विकसित हुए और सुदृढ़ राजनीतिक संस्थानों की अनुपस्थिति में किस तरह काम करते हुए विकसित हुए, इसकी हमारी समझ बढ़ाने में भी मददगार रही। ये राजनीतिक संस्थान सरकार और बाजार के बीच की सीमारेखा को स्पष्ट रूप से बनाए रखते हैं। विश्लेषणात्मक रूप से, यह शोध अध्ययन निरंकुश शासन की एकल शासन के रूप में मॉडलिंग की सीमाओं को रेखांकित करता है और निरंकुश शासन तथा संगठनात्मक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए संगठनात्मक दृष्टि को दिखाता है।

सैद्धांतिक रूप से, यह अध्ययन वित्त की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए स्थान संबंधी और प्रायोगिक दृष्टि के उपयोग का महत्त्व बताता है। और आखिर में, यह अध्ययन चीन की औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के विकास को व्यवस्थित तरीके से समझने का एक प्रथम प्रयास भी है, जिसके लिए अब तक "सरकारी स्वामित्व" जैसी साधारण टर्म का प्रयोग होता आया था। इस प्रकार, यह अध्ययन चीन में नीति निर्माण और केंद्रीय-स्थानीय राजनीति को समझने में भी मदद करता है। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण–व्यवस्थाएं

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है, जो उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं। एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इनके अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल के शिपमेंट पर भारतीय निर्यातक को संविदा मूल्य के 100% की प्रतिपूर्ति करता है, बशर्ते कि कुल संविदा मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत के माल एवं सेवाओं का शिपमेंट भारत से किया गया हो। ऋण-व्यवस्थाओं के जरिए उभरते बाजारों में भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता के प्रदर्शन में भी मदद मिली है। हाल के वर्षों में ऋण-व्यवस्थाओं ने गति पकड़ी है। विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। बैंक द्वारा 14 दिसंबर, 2020 तक अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशियानिया और सीआईएस क्षेत्रों के 62 देशों को 26.59 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धता के साथ 266 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जो भारत से निर्यातों के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं विकासशील देशों में भारत से परियोजनाओं, माल और सेवाओं के निर्यात के संवर्धन और सुगमीकरण के लिए प्रभावी साधन हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने सितंबर–दिसंबर 2020 के दौरान भारत सरकार की ओर से निम्नलिखित दो ऋण–व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए:

i गिनी गणराज्य सरकार को कनकन और ज़ैरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पतालों की निर्माण एवं उन्नयन परियोजना के वित्तपोषण के लिए 20.506 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से गिनी सरकार को अब तक 245.73 मिलियन यूएस डॉलर की कुल चार ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं गिनी सरकार को 130 बेड वाले प्रसूति अस्पतालों, सौर परियोजनाओं के निर्माण एवं स्थापना के लिए और ग्रांड कोनाक्री-होराइजन 2040 पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई हैं।

ii. मालदीव गणराज्य सरकार को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के वित्तपोषण लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई। इस एलओसी करार पर हस्ताक्षर के साथ, एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार को अब तक 1240 मिलियन यूएस डॉलर की कुल तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं। मालदीव सरकार को प्रदान की गई इन ऋण-व्यवस्थाओं को अंतर्गत कवर की जाने वाली परियोजनाओं में 485 आवासीय घरों का निर्माण और सड़क विकास तथा अन्य विकास परियोजनाएं शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए:

श्री गौरव भंडारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
ऑफिस ब्लॉक, टॉवर1, 7वीं मंज़िल, एड्जेसेंट रिंग रोड
किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023
फोन: (011) 24607700
ईमेल: eximloc@eximbankindia.in

दास्तान–ए–कामयाबी

गाम्बिया सरकार को प्रदत्त ऋण–व्यवस्था के अंतर्गत विद्युतीकरण विस्तार परियोजना

बैंक ने गाम्बिया सरकार को विद्युतीकरण विस्तार परियोजना के लिए 22.50 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था के प्रदान की है। इसके कार्य क्षेत्र में गाम्बिया के ग्रेटर बांजुल क्षेत्र में विद्युतीकरण संबंधी कार्य का विस्तार शामिल है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य निम्नलिखित अनुसार हैं:

- जबांग में 33/11 केवी के नए इनडोर प्राइमरी सब स्टेशन का निर्माण;
- ब्रिकमा में 33/11 केवी के नए इनडोर प्राइमरी सब स्टेशन का निर्माण;
- 33 केवी की ओवरहैड वितरण प्रणाली का निर्माण / विस्तार;
- 11 केवी की ओवरहैड वितरण प्रणाली का निर्माण / विस्तार;
- 33/0.4 और 11/0.4 केवी के नए सेकेंडरी सबस्टेशन का निर्माण और;
- नई एलवी ओवरहैड वितरण प्रणाली का निर्माण। ■

तिमाही गतिविधियां

बेहतर सहयोग और नए क्षेत्रों को चिह्नित कर और मजबूत किए जा सकते हैं भारत-जीसीसी संबंध: इंडिया एक्ज़िम बैंक

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने बैंक द्वारा आयोजित "भारत-जीसीसी संबंधों को बढ़ानाः परियोजना निर्यात और अन्य संभावनाएं" विषयक वेबिनार के दौरान "जीसीसी के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ानाः व्यापार, प्रवासन और रेमिटैंस में रुझान" विषयक अपने शोध अध्ययन का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान ओमान में भारत के माननीय राजदूत श्री मुनु महावर, कतर में भारत के माननीय राजदूत श्री दीपक मित्तल, बहरीन में भारत के माननीय राजदूत श्री पीयूष श्रीवास्तव और कुवैत में भारतीय दूतावास, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड तथा एफ्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अध्ययन में भारत-खाड़ी क्षेत्र के आर्थिक संबंधों में सहयोग के दो अलग क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है। इनमें द्विपक्षीय व्यापार, विशेष रूप से कमोडिटी व्यापार और भारत से प्रवासन जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिससे खाड़ी क्षेत्र में बड़ा प्रवासी समुदाय बन रहा है।

श्री एन. रमेश ने संभाला एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक का कार्यभार

श्री एन. रमेश ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वह 1999 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी हैं। इंडिया एक्ज़िम बैंक में नियुक्ति से पहले वह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। 2016 से 2019 तक वह वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। यहां उन्होंने कृषि, निर्यात, बायोटेक्नोलॉजी और संयंत्र प्रभागों का कार्यभार संभाला। 2010-2016 के दौरान श्री एन. रमेश ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में निदेशक (मार्केटिंग) के रूप में अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने दूरसंचार विभाग में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और बीपीओ उद्योग संबंधी लाइसेंसिंग शर्तों और विनियमन के क्रियान्वयन के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने मोबाइल नेटवर्क और संबंधित बुनियादी ढांचागत विकास के लिए बीएसएनएल के साथ भी काम किया है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक का आकलन: अफ्रीका में 5 भारतीय अस्पताल और क्षेत्रीय हेल्थकेयर हब बनाने की तत्काल आवश्यकता

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूरे विश्व की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली गंभीर दबाव में है। आकलन के अनुसार, अफ्रीका के स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम 66 बिलियन यूएस डॉलर प्रति वर्ष की कमी है। यह दर्शाता है कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता और डोनर फंडिंग जैसे परंपरागत उपाय अपर्याप्त हैं। इस क्षेत्र में बीमारियों से भारी संख्या में जनहानि को रोकने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। "भारत-अफ्रीका संवादः स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संभावनाएं" विषय पर आयोजित आज के वेबिनार में इन सुझावों पर चर्चा की गई। वेबिनार में मॉरीशस के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के स्थायी उप सचिव श्री गुलशन रामरेखा सहित कई गणमान्य हस्तियां शामिल रहीं। श्री रामरेखा ने मॉरीशस के माननीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉ. कैलाश कुमार जगतपाल का संदेश पढ़ा। भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (ईआर) श्री राहुल छाबड़ा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अफ्रीका में क्षेत्रीय केंद्रों पर केंद्रित सत्र में भारत में मोरक्को के माननीय राजदूत श्री मोहम्मद मलिकी; बोत्सवाना गणराज्य के माननीय उच्चायुक्त श्री गिलबर्ट शिमेन मंगोल; सेनेगल (वर्तमान में गाम्बिया, गिनी बिसाऊ और काबो वेर्दे सहित) में भारतीय राजदूत श्री जी.वी. श्रीनिवास; और युगांडा (वर्तमान में बुरुंडी सहित) के लिए भारतीय उच्चायुक्त श्री ए. अजय कुमार शामिल रहे। वेबिनार के दौरान, एक सत्र भारत की विकासात्मक भूमिका को आकार देने में अहम, भारतीय निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा अनुभव साझा करने का भी रखा गया। इस सत्र में नारायण हेल्थ के चेयरमैन डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी; एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री के बी जॉर्ज; अपोलो हॉस्पिटल्स के अस्पताल प्रभाग के अध्यक्ष डॉ. के. हरि प्रसाद; और एलएंडटी कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के वाइस प्रेसीडेंट और हेड, श्री वी. सुकुमार हेब्बर शामिल रहे।

व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक और बैंक ऑफ अफ्रीका बीएमसीई ग्रुप ने किए एमओयू पर हस्ताक्षर

भारत और मोरक्को के बीच आर्थिक संबंधों के महत्व और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने बैंक ऑफ अफ्रीका बीएमसीई ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू की घोषणा दोनों संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत-मोरक्को व्यापार मंच के दौरान की गई थी। इस वर्चुअल रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि मोरक्को में भारत के राजदूत महामहिम मोहम्मद मालिकी तथा मोरक्को में भारतीय दूतावास के उप राजदूत श्री जी. के. पंत उपस्थित रहे।

एक्ज़िम बैंक का पूर्वानुमान, वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में भारत का गैर-तेल निर्यात 68.3 बिलियन की मामूली सकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर्ज करेगा

इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के लिए पूर्वानुमान के अनुसार भारत का गैर-तेल निर्यात पिछले वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 0.3% की मामूली सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 68.3 बिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर, 2020-21 की तीसरी तिमाही में कुल मर्चेंडाइज निर्यात 77.6 बिलियन यूएस डॉलर आंका गया है, जो गत वर्ष की इसी तिमाही में यह 79 बिलियन यूएस डॉलर था। यह मार्च 2020 से भारत के तेल निर्यातों में हुई लगातार और भारी गिरावट के परिप्रेक्ष्य में है। यह पूर्वानुमान एक्ज़िम बैंक के एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ई एल आई) मॉडल पर आधारित है। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

मोरक्को

मोरक्को के वास्तविक जीडीपी में 2020 में 6.9% की दर से गिरावट की आशंका है। महामारी के कारण पर्यटन क्षेत्र का लगभग पूरी तरह बंद रहना और आर्थिक परिदृश्य का बिगड़ना इसका प्रमुख कारण है। हालांकि 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार में सुधार के साथ वास्तविक जीडीपी में 3.8% की दर से सुधार की संभावना है। जीडीपी में 15% से अधिक का योगदान देने वाले और रोजगारों में 30% से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले कृषि क्षेत्र को 2020 में सूखे के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा। माहमारी के चलते विशेष रूप से यूरोप को ऑटोमोटिव क्षेत्र से निर्यातों में आई रुकावट के चलते 2020 में औद्योगिक उत्पादन में भी गिरावट देखी गई। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में 2019 की 0.2% की तुलना में 2020 में खाद्य कीमतों और घरेलू मांग में सुधार के चलते 0.7% की दर से बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय मांग में गिरावट के चलते 2020 में निर्यात आय में गिरावट के बाद 2021 में विदेशों से मांग बढ़ने पर मोरक्को के निर्यातों में वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्चतर-मूल्य निर्यात उन्मुख विनिर्माण (विशएष रूप से ऑटोमोटिव और एयरोनॉटिक्स उद्योगों से) उत्पादन बढ़ने के कारण रहेगी। अतः चालू खाता घाटा 2020 के 7.2% की तुलना में 2021 में घटकर 5.7% होने की संभावना है।

गयाना

तेल की खोज के साथ ही 2020 में तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से गयाना के वास्तविक जीडीपी के 2020 में 24% और 2021 में 10% की दर से बढ़ने की संभावना है। अतिरिक्त ऑफशोर तेल भंडारों के मिलने से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र और संबंधित बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। तथापि, महामारी के चलते इस निवेश की पहले आंकी गई गति से कमतर होगी। चीनी उद्योग को मजबूती मिलने और बॉक्साइट तथा स्वर्ण खनन में नई क्षमता के चलते गैर-तेल वृद्धि भी बढ़ेगी। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2019 की 2.1% की तुलना में 2020 में कोरोना वायरस और वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के चलते 0.7% रहने के आसार हैं। 2020-23 के दौरान गायाना डॉलर के 1 यूएस डॉलर की तुलना में 208.1 के स्तर पर बने रहने की संभावना है। तेल की खोज से विदेशी क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे संरचनात्मक घाटा आने वाले वर्षों में अधिशेष (सरप्लस) में तब्दील हो सकता है। समग्र चालू खाता घाटा 2020 में बढ़कर जीडीपी के 18.2% तक पहुंचने के आसार हैं। हालांकि 2021 में यह घटकर 2.8% तक रह सकता है। फिर 2022 में चालू खाता जीडीपी के 6.7% के स्तर पर अधिशेष में बदल सकता है।

कैमरून

कोविड-19 के चलते वैश्विक मंदी के बीच 2020 में कैमरून की अर्थव्यवस्था में 2.9% की दर से गिरावट की आशंका है। वस्तु मूल्यों, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का यहां की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। फिक्स्ड निवेशों और निर्यातों की मात्रा में गिरावट से निजी खपत में भी गिरावट आई है। औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 2019 की 2.5% की तुलना में 2020 में 2.9% तक रहने की संभावना है, क्योंकि क्षेत्रीय गतिरोधों के चलते खाद्य उत्पादन बाधित हुआ, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। कैमरून की मुद्रा सीएफए फ्रैंक जो 1 यूरो के मुकाबले 655.96 के स्तर पर स्थिर है। सीएफए फ्रैंक 2019 की 1 यूएस डॉलर की तुलना में 586.0 से कुछ मजबूत होकर 2021 में 576.3 सीएफए फ्रैंक होने की संभावना है, क्योंकि 2021 में डॉलर के मुकाबले में यूरो के कुछ मजबूत होने के आसार हैं। चालू खाता घाटा 2019 में जीडीपी के 4.4% से बढ़कर 2020 में जीडीपी के 7.5% तक होने की आशंका है। हालांकि व्यापार घाटा कम होने के अनुरूप, 2024 में इसके धीर-धीरे कम होकर जीडीपी के 3.9% तक पहुंचने के आसार हैं। माना जा रहा है कि महामारी के नियंत्रण में आने, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संभलने और तेल की कीमतें बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि दर 2021 में 2.5% तक होने की संभावना है।

मालदीव

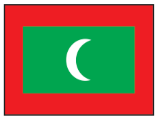

मालदीव के जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है और यह देश की आर्थिक विकास दर का प्रमुख कारक है। मालदीव आने वाले पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या चीनी पर्यटकों की होती है। 2019 में कुल पर्यटकों में से पाँचवां हिस्सा चीनी पर्यटकों का ही था। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र की प्रभावी भूमिका को देखते हुए 2021-22 में अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और यात्राओं पर खर्च बढ़ने से यहां की आर्थिक वृद्धि में भी सुधार होगा। 2019 में 6.9% की दर से विकसित होने वाली मालदीव की अर्थव्यवस्था के 2020 में 29.5% तक संकुचित होने के बाद 2021 में 21% की दर से आंशिक रूप से रिकवर होने की उम्मीद है। पर्यटकों के पहुंचने के अलावा निर्माण गतिविधियों में तेजी आना और धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां बढ़ना, इस वृद्धि के मुख्य कारक होंगे। पर्यटन का रुकना, मंद आर्थिक गतिविधि, आवश्यक खाद्य वस्तुओं का मूल्य नियमन और अन्य सुविधाओं के बिलों से 2020 में मुद्रा अवस्फीति का परिवेश बना। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में 2019 की 0.2% की तुलना में 2020 में औसतन -1.7% की दर से गिरावट के आसार हैं। मत्स्य निर्यातों और पर्यटन आय में गिरावट से चालू खाता घाटा 2019 में जीडीपी के 25.9% से बढ़कर 2020 में जीडीपी का 27.9% होने के आसार हैं। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

सऊदी अरब रियाल

SR गोल्डमैन साक्स ग्रुप इंक. के अनुसार, सऊदी अरब कच्चे तेल की गिरती कीमतों के बीच गैर-तेल आर्थिक वृद्धि के मुकाबले अपनी मुद्रा रियाल में स्थिरता को बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीतियां बनाता रहा है। रियाल को वर्तमान स्तर पर बनाए रखना सऊदी अरब के लिए प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता है। तेल की निम्न कीमतों वाले परिवेश में मुद्रा की स्थिरता के साथ विदेशी बैलेंस को यथावत बनाए रखने के लिए बजट घाटे को नियंत्रित रखते हुए राजकोषीय नीतिगत सख्ती बरतना वांछनीय है। सऊदी अरब अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है और यूएस फेडरल रिज़र्व के हर कदम की करीब से निगरानी रखता है। हालांकि, इस वर्ष कच्चे तेल की कीमतें गिरने से दबाव बढ़ गया था और तब से सऊदी रियाल के लिए 12 महीने का डॉलर-वायदा स्थिर है।

देश का संप्रभु कोष अब भी वित्तीय रूप से सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। देश को अपनी निवेश योजनाएं लागू करने के लिए सरकारी कोष से पूंजी लगानी ही पड़ती है। तेल की कीमतें बढ़ने से इस स्थिति में सुधार आएगा और सरकार विदेशी बैलेंस के साथ समझौता किए बिना खर्च बढ़ा पाएगी। कोरोना वायरस फैलने से भी पहले के समय से सऊदी अरब की मुद्रा रियाल एक डॉलर के मुकाबले 3.7489 और 3.7518 के बीच बनी रही है। इसमें केवल मार्च 2020 से जून 2020 के बीच में ही थोड़ी गिरावट आई थी। 21 दिसंबर, 2020 को यह 3.7516 के स्तर पर रही।

इंडोनेशियाई रुपैया

Rp कोविड-19 का असर दो दशकों की तीव्र आर्थिक वृद्धि पर पड़ा है। इस महामारी के चलते इंडोनेशिया की शिक्षा व्यवस्था में सुधार संबंधी योजनाओं और प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में भी काफी देरी हुई है। इसमें देश की राजधानी को जकार्ता से बोर्निओ द्वीप ले जाने संबंधी 33 बिलियन यूएस डॉलर की परियोजना भी शामिल है। इससे देश के मध्य आय वर्ग वाले संजाल से बचने के प्रयासों को धक्का लगा है। इंडोनेशिया तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की कतार में शामिल होने के लिए प्रयासरत है, ताकि वह मध्य आय वर्ग वाले देशों की कतार से निकलकर उच्च आय वर्ग वाले देशों की फेहरिस्त में शामिल हो सके और 2045 तक दुनिया की पांच शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में उसका भी नाम लिया जाए।

केंद्रीय सांख्यिकी एजेंसी अथवा बीपीएस के अनुसार, इस महामारी से अगस्त तक देश में 2.67 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी दर बढ़कर 7.1% हो गई यानी देश में 9.8 मिलियन लोग बेरोज़गार हो गए। जबकि एक वर्ष पहले बेरोजगारी दर 5.23% थी। 2011 के बाद यह पहली बार है जब इंडोनेशिया की बेरोजगारी दर 7% से अधिक रही है।

वर्ष के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले इंडोनेशियाई रुपैया 16,620 (23 मार्च, 2020) से 13,810 (08 जून, 2020) के स्तर पर भी रहा। हालांकि बाद में मुद्रा में स्थिरता आ गई और 21 दिसंबर, 2020 को यह यूएस डॉलर के मुकाबले 14,100 के स्तर पर रहा।

सिंगापुर डॉलर

S$ आने वाले समय में कोरोना वायरस के टीके के परीक्षणों में आने वाली तेजी के चलते सिंगापुर में आर्थिक सुधारों में तेज़ी आने के आसार हैं। स्ट्रेट टाइम्स ने लिखा है कि सिंगापुर को अगले साल तक यूएस और स्थानीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कोरोना वायरस का टीका मिल सकता है और इस टीके की पहली खेप 2021 की पहली तिमाही में ही पहुंच सकती है।

महत्त्वपूर्ण आधार के टूटने के बावजूद सिंगापुर डॉलर, यूएस डॉलर के मुकाबले जनवरी 2020 में 1.3445 के स्तर पर पहुंचा, जो नवंबर 2019 के 1.3444 के स्तर के आसपास रहा। यह गिरावट तुलनात्मक रूप से खास नहीं रही। हालांकि 2021 की पहली तिमाही में गिरावट की आशंका है, तथापि गिरावट की गति धीमी रहने के आसार हैं। फिर भी उम्मीद की जा रही है कि यह गिरावट 2018 के 1.3008 के स्तर से नीचे नहीं जाएगी। इसे 1.3300 के बाद 1.3200 का मजबूत सपोर्ट है।

मुद्रा की मजबूती की बात करें तो गिरावट का ट्रेंड और 55 हफ्ते का औसत (क्रमशः 1.3630 और 1.3730) मजबूत सुरक्षा कवच की भूमिका में हैं और वर्तमान गिरावट को देखते हुए इस सुरक्षा कवच के टूटने की संभावना कम ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि ये दोनों स्तर समय के साथ निम्नतर हो रहे हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले सिंगापुर डॉलर 17 दिसंबर, 2020 को 1.3244 के न्यून स्तर पर पहुंच गया था और फिर 21 दिसंबर, 2021 को थोड़ा मजबूत होकर 1.3323 के स्तर पर रहा।

वियतनामी डोंग

₫ 16 दिसंबर, 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी ने स्विट्ज़रलैंड और वियतनाम पर अपनी मुद्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, ताकि वे अमेरिकी निर्यातों पर व्यापार का लाभ ले सकें। यूएस ट्रेजरी ने अपनी अर्धवार्षिक विदेशी मुद्रा विनिमय रिपोर्ट में पाया कि ये दोनों देश भुगतान शेष को प्रभावित करने के लिए मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहे थे और वियतनाम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनैतिक रूप से प्रतिस्पर्धी लाभ कमाना था। यूएस ट्रेजरी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया मूल्यांकन में इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वियतनामी डोंग 2018 में वास्तविक प्रभावी आधार की तुलना में 8.4% तक अंडरवैल्यूड रहा और तब से यूएस डॉलर के मुकाबले वर्चुअली फ्लैट रहा। रिपोर्ट में वियतनाम से "अपनी मुद्रा का हस्तक्षेप कम करने और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होने देने" की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में वियतनाम को अमेरिकी कंपनियों और निर्यातों के लिए बैरियर हटाने के लिए भी कहा गया है।

वियतनामी डोंग 21 दिसंबर, 2021 को यूएस डॉलर के मुकाबले 23,120 पर बंद हुआ, जो 17 दिसंबर, 2020 के 23,115 के स्तर के आसपास रहा। 24 मार्च, 2020 को यह यूएस डॉलर के मुकाबले 23,580 के उच्च स्तर पर था। ■

एक्ज़िम मित्र

नारियल निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में जानकारी

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने नारियल की छाल और फाइबर से बने उत्पादों को छोड़कर अन्य समस्त उत्पादों के लिए नारियल विकास बोर्ड को निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में अधिसूचित किया है। नारियल के निर्यातकों को विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रियायतों और शुल्क रहित योजनाओं का लाभ लेने के लिए नारियल विकास बोर्ड से रजिस्ट्रेशन-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र लेना जरूरी है।

निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के बारे में जानकारी

ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम) की स्थापना, ऋण जोखिम बीमा और निर्यातों के लिए संबंधित सेवाएं प्रदान करते हुए देश से निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1957 में की गई थी। इसका प्रशासनिक नियमन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग, बीमा और निर्यातक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समय के साथ, ईसीजीसी लिमिटेड ने भारतीय निर्यातकों और निर्यात ऋण प्रदान करने वाले वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न ऋण जोखिम बीमा उत्पाद विकसित किए। यह निर्यात संबंधी गतिविधियों में मार्गदर्शन भी करता है। ईसीजीसी के मुख्य कार्य हैं:

- क्रेडिट रेटिंग के जरिए विभिन्न देशों में जोखिमों की सूचना उपलब्ध कराता है।
- बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से निर्यात वित्त हासिल करने को आसान बनाता है।
- फंसे हुए कर्जों की वसूली करने में निर्यातकों की मदद करना।
- विदेशी क्रेताओं की ऋण-पात्रता संबंधी सूचना प्रदान करना।

उत्पत्ति (मूल) स्थान के प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी

उत्पत्ति (मूल) स्थान का प्रमाण किसी देश में आयातित माल के मूल स्थान का प्रमाण पत्र देने वाला दस्तावेज है। ये प्रमाण पत्र निर्यातकों के लिए अनिवार्य हैं, ताकि वे साबित कर सकें कि उनका माल किस स्थान का है और आयातक देश में भारतीय माल पर मिलने वाले लाभ का फायदा उठा सकें।

उत्पत्ति के मूल स्थान पर निर्यातक द्वारा 10 रुपये के गैर-अदालती स्टाम्प पेपर पर स्थायी क्षतिपूर्ति बॉन्ड के साथ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, जिसे विधिवत नोटराइज किया गया हो। इस प्रमाण पत्र पर चैंबर ऑफ कॉमर्स या किसी अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर होना और मुहर लगी होना आवश्यक है। यह वस्तुओं की उत्पत्ति प्रमाणित करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है।

इन्कोटर्म्स नियम कैसे निर्धारित किए जाते हैं

इन्कोटर्म्स 2020 में 11 नियम हैं। इन्हें दो खंडों में विभाजित किया गया है। इनमें से 7 परिवहन के किसी भी माध्यम या माध्यमों के जरिए और 4 समुद्री तथा अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा परिवहन के लिए हैं। प्रत्येक नियम के शीर्षक में तीन अक्षरों वाला संक्षिप्त नाम है, इसके बाद उस नियम का नाम है और फिर इनके उपयोग का सही तरीका। अर्थात् संक्षिप्त नाम के बाद संबंधित स्थान बताया गया है। यहां इन नियमों के 11 शीर्षक नीचे दिए गए हैं।

परिवहन के माध्यम या माध्यमों के लिए नियम

1. एक्सडब्ल्यू एक्स वर्क्स (डिलीवरी के स्थान का नाम बताता है)
2. एफसीए - फ्री कैरियर (डिलीवरी के स्थान का नाम बताता है)
3. सीपीटी कैरिज पेड टू (गंतव्य स्थान का नाम बताता है)
4. सीआईपी कैरिज इंश्योरैंस पेड (गंतव्य स्थान का नाम बताता है)
5. डीएपी डिलीवर्ड एट प्लेस (गंतव्य स्थान का नाम बताता है)
6. डीपीयू - डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड (गंतव्य स्थान का नाम बताता है)
7. डीडीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड (गंतव्य स्थान का नाम बताता है)

समुद्री और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए नियम

8. एफएएस - फ्री अलॉन्गसाइड शिप (लोडिंग बंदरगाह का नाम बताता है)
9. एफओबी फ्री ऑफ बोर्ड (लोडिंग बंदरगाह का नाम बताता है)
10. सीएफआर कोस्ट एंड फ्रेट (गंतव्य बंदरगाह का नाम बताता है)
11. सीआईएफ - कोस्ट इंश्योरैंस एंड फ्रेट (गंतव्य पोर्ट का नाम बताता है)

प्रत्येक नियम में एक रेखाचित्र दिया गया है। इनमें नीला रंग विक्रेता के दायित्वों को दर्शाता है। स्वर्ण रंग खरीदार के दायित्वों को और कुछ नियमों में हरा रंग दोनों के समान दायित्वों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य यही है कि पाठकों को हर नियम समझने में आसानी हो। स्वाभाविक है कि ये रेखाचित्र वास्तविक नियमों का हिस्सा नहीं हैं। ■

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

वस्तु व्यापार

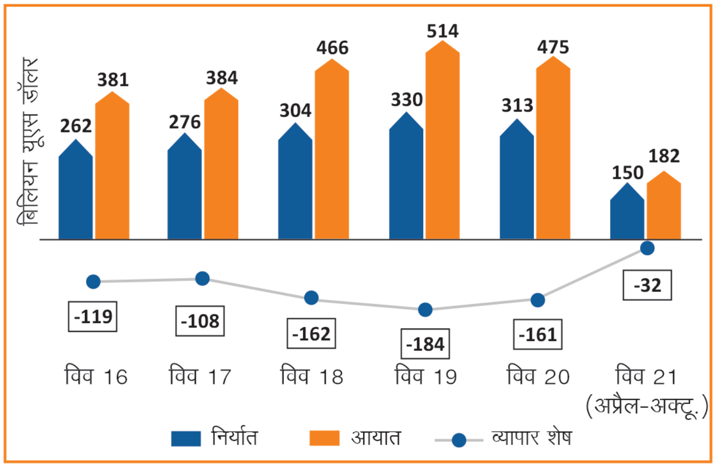

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

सेवाएं व्यापार

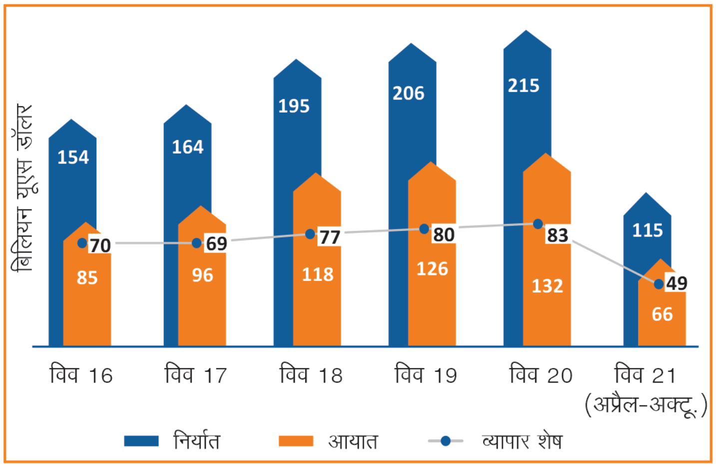

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह

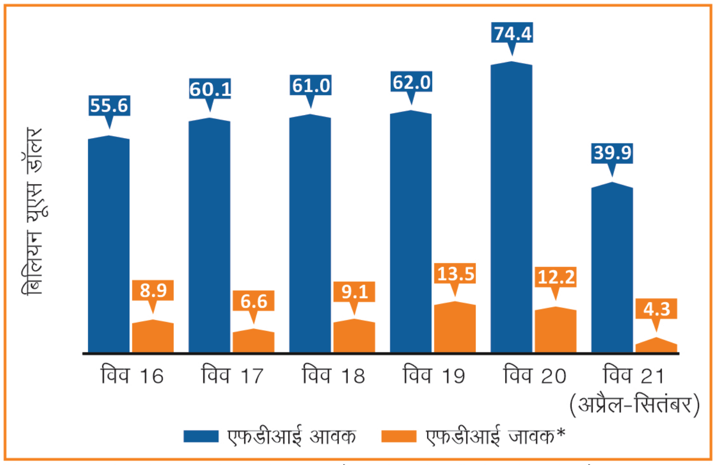

नोट: - एफडीआई जावक में इक्विटी, ऋण और इन्वोक की गई गारंटियां शामिल हैं।*
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (सीपीआई)

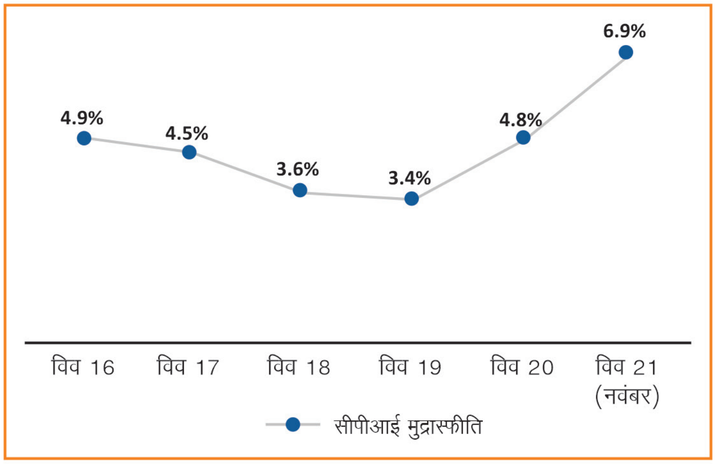

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

चालू खाता घाटा

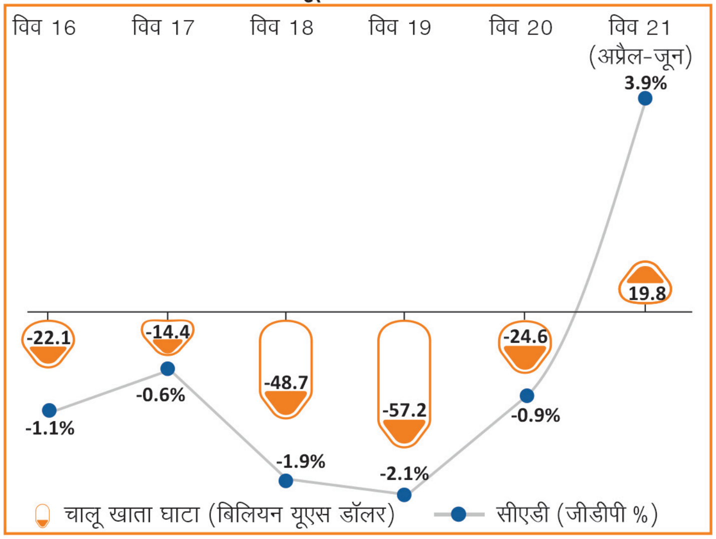

स्रोत: आरबीआई

क्षेत्रवार उत्पादन

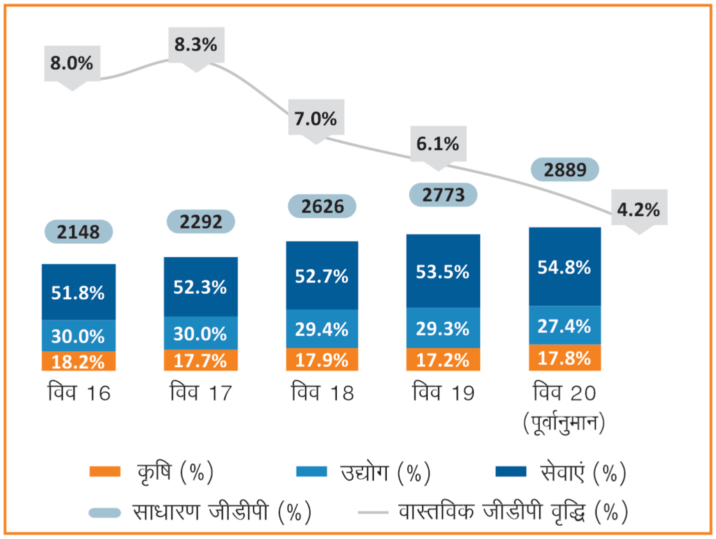

स्रोत: आईआईएफ और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय